RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 30 MARCH 2022 TO 05 APRIL 2022 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 30 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

ONGC की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
Page 2

एडलवाइस ने मध्य प्रदेश में अपने ग्राहकों की संख्या 362% बढ़ाई
Page 3

किर्लोस्कर मोटर्स ने 'हाई-एफिशिएंसी लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक मोटर्स' लॉन्च किया
Page 7

editoria!

निर्यात में वृद्धि

चार सौ अरब डॉलर मूल्य के निर्मित उत्पादों के निर्यात लक्ष्य का पूरा होना अनेक अर्थों में बड़ी उपलब्धि है. यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इसे रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा है कि भारतीय वस्तुओं की वैश्विक मांग बढ़ रही है तथा यह देश की क्षमता एवं संभावना को इंगित करता है. उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संभालने और उसे पटरी पर बनाये रखने के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह की नीतियों और कार्यक्रमों का सूत्रपात किया था. इसके साथ ही वंचित तबके, उद्यमियों तथा उद्योग जगत को राहत देने के लिए कल्याणकारी और वित्तीय पहलें हुई थीं. इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया था. उन्होंने स्थानीय उत्पादों के उपभोग के लिए 'वोकल फॉर लोकल' तथा घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुकूल बनाने के लिए 'लोकल फॉर ग्लोबल' का सूत्र दिया था. निर्यात बढ़ाने के लिए हुए अनेक प्रयासों में एक यह भी था कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता दी जाए. इन कोशिशों के सकारात्मक परिणाम अब हमारे सामने हैं. निर्यात वृद्धि का एक विशेष पहलू यह है कि दुनिया हमारे उत्पादों को पसंद कर रही है. कोरोना काल में भारत समेत पूरे विश्व के सामने आपूर्ति श्रृंखला के बड़े हिस्से के किसी एक या कुछ देशों में केंद्रित होने की समस्याओं का पता चला. इस श्रृंखला को विकेंद्रीकृत करने के प्रयासों में भारत एक विशेष स्थान रखता है. कारोबारी सुगमता, अर्थव्यवस्था के ठोस आधार, नीतिगत सुधार, कराधान में बेहतरी और स्थिरता जैसे कारकों की वजह से विदेशी निवेशक और कंपनियां भारत के प्रति आकर्षित हुई हैं. यही कारण है कि कोरोना काल में भी भारत में बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है. प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया है कि उत्पादन और निर्यात में बेहतरी हमारे देश की आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को भी दर्शाती है. यह भी ध्यान रखना चाहिए कि निर्यात में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब वैश्विक स्तर पर कई कारणों से आपूर्ति में व्यवधान है तथा माल ढुलाई में मुश्किलें आ रही हैं. रूस-यूक्रेन संकट ने स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है. निश्चित रूप से इसके नकारात्मक प्रभाव भारत पर भी हो रहे हैं और आगे की स्थिति के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक पक्ष यह भी है कि अन्य कई उत्पादों के साथ अनाज, दवा जैसी भारतीय वस्तुओं के लिए बाजार भी बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस विशेष आयाम को भी अभिव्यक्त किया है कि निर्यात वृद्धि में आर्थिक गतिविधियों में लगे हर समूह का योगदान रहा है. यदि पूरा देश स्थानीय उत्पादों का उपभोग करे और उनकी गुणवत्ता बढ़ाकर दुनिया के सामने रखे, तो निर्माण एवं निर्यात के स्तर में भारत बड़ी छलांग लगा सकता है.

रुपये में रूस से कच्चा तेल खरीदेगा भारत? संसद में मंत्री ने कही ये बात

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल के लिए रुपये में भुगतान करने की कोई योजना नहीं है। संसद को सोमवार को यह जानकारी दी गई। भारत अपने कुल तेल आयात का एक प्रतिशत से भी कम रूस से खरीदता है। लेकिन यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों ने तेल और गैस की खरीद के लिए रुपये में व्यापार का रास्ता मुहैया कराया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ''मौजूदा समय में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का न तो कोई अनुबंध है और न ही रूस या किसी अन्य देश से भारतीय रुपये में कच्चे तेल की खरीद करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।' उन्होंने इसके बारे विस्तार से जानकारी नहीं दी है।

सूत्रों ने कहा कि रूस के साथ व्यापार डॉलर में तय किया जा रहा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय भुगतान तंत्र को अब तक पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा ईरान पर उसके विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के विपरीत रूस के साथ तेल और ऊर्जा व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि कोई भी देश या कंपनी रूस से तेल और अन्य ऊर्जा संसाधन खरीदने और व्यापार को निपटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। ईरान के मामले में ऐसा नहीं था, जिसे अंतरराष्ट्रीय धन और सुरक्षा हस्तांतरण प्रणाली, 'स्विफ्ट' से 'काट' दिया गया था। साथ ही ईरान से तेल का निवेश करने या खरीदने वाली कंपनियों या संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

लगातार गिरावट के बाद सोना फिर हुआ महंगा

नयी दिल्ली। एजेंसी

ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव की वजह से बुधवार को भारतीय बाजार में भी सोने-चांदी की कीमतों में उछाल आया। सोने का भाव एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था, जो वापस चढ़ रहा है। एमसीएक्स पर आज सोने की कीमत 0.45 फीसदी बढ़कर 51,518 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई है, वहीं चांदी के दाम में 0.21 फीसदी की तेजी आई है। इसके बाद चांदी का भाव उछलकर 67,085 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। यहां बता दें कि आभूषण बनाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट का ही इस्तेमाल होता है। कुछ लोग 18 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल करते हैं। आभूषण पर कैरेट के हिसाब से हॉल मार्क बना होता है। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है।

अभी और बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम!

धीरे-धीरे होगा कीमतों में इजाफा

नई दिल्ली। एजेंसी

उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं। जिसके बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल (झ्रूदत्-अगोत ईग्म) की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 22 मार्च से अबतक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सातवीं बार इजाफा देखने को मिला है। लेकिन भविष्य में राहत की उम्मीद कर रहे लोगों के लिए बड़ा झटका है। सूत्रों के अनुसार तेल की कीमतों में इजाफा होता रहेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार एक साथ कीमतों में इजाफा कर नागरिकों को बड़ा झटका देने से बच रही है। यही वजह है कि कीमतों में बढ़ोतरी धीरे-धीरे होगी। दीपावली से पहले केन्द्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई थी। फिर बाद में राज्य सरकारों की तरफ से भी कीमतों को घटाया गया था। पांच राज्यों में चुनाव के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला था। लेकिन अब एक बार फिर से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

डीए में तीन फीसदी बढ़ोतरी

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में तीन फीसदी बढ़ोतरी का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया है। यह एक जनवरी 2022 से लागू होगा। इससे करीब 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर हर साल 9544.50 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA साल में दो बार जनवरी से जुलाई के बीच अपडेट किया जाता है। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके DA का कैलकुलेशन किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ॐ दिया जाता है। यह कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है। डीए में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में पिछले कई दिनों से बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत पिछले नौ दिनों में आठ किस्तों में 5.60 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुकी है। इससे महंगाई का खतरा बढ़ गया है।

कितना होगा फायदा

पिछले साल जुलाई में भी डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी और यह बढ़कर 31 फीसदी हुआ था। अब इसे बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया है। डीए में बढ़ोतरी से अब 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ता 6,120 रुपये हो जाएगा। इसी तरह अधिकतम सैलरी स्लैब वाले कर्मचारियों का डीए बढ़कर 19,346 रुपये प्रति माह हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 18 महीने यानी एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए का भुगतान नहीं किया है। कर्मचारी लंबे समय से इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं।

पेट्रोल पर मोदी सरकार ने 5 रुपये टैक्स घटाकर जो राहत दी थी, उसका असर अब खत्म, 9 दिन में ही 5.60 रुपये महंगा हुआ तेल

नई दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोल पर मोदी सरकार ने 5 रुपये टैक्स घटाकर जो राहत दी थी, उसका असर अब खत्म, 9 दिन में ही 5.60 रुपये महंगा हुआ तेल पेट्रोल-डीजल के दाम पिछले 9 दिनों में ही 5 रुपये 60 पैसे तक बढ़ गए हैं। पांच महीने पहले ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की राहत जो उपभोक्ताओं को दी थी, उसका असर अब खत्म हो गया है।

अब 22 मार्च 2022 से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 22 मार्च से 23 मार्च तक रोजाना पेट्रोल-डीजल 80-80 पैसे महंगा हुआ। 24 मार्च को कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 25 मार्च से एक बार फिर पेट्रोल-डीजल 26 तक 80-80 पैसे बढ़े। इसके बाद 27 मार्च को पेट्रोल 50 और डीजल 55 पैसे महंगा हुआ। 28 मार्च को पेट्रोल 30 और डीजल 35 पैसे बढ़ा। 29 मार्च को पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया और आज यानी 30 मार्च को एक बार फिर पेट्रोल-डीजल के दाम 80-80 पैसे बढ़े हैं।

श्रीगंगानगर और मुंबई में तो डीजल भी 100 के पार

मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल के दाम पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गए हैं। ज्यादातर राज्यों की राजधानी में भी पेट्रोल 'शतक' के लगा चुका है। श्रीगंगानगर और मुंबई में तो डीजल भी 100 के पार चला गया है। पेट्रोल-डीजल के दाम अभी कम होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए का इजाफा करना होगा। इस लिहाज से देखें तो पेट्रोल-डीजल की कीमत में अभी और 18 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।

वहीं, पिछले दिनों मूडीज रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट जारी कर कहा था कि भारत के टॉप फ्यूल रिटेलर्स आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को नवंबर से मार्च के बीच करीब 19 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। ऐसे में कंपनियां घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम एक बार में न बढ़ाकर धीरे-धीरे बढ़ाएंगी। बता दें केंद्र सरकार के टैक्स घटाने के बाद कई राज्यों ने भी वैट को कम किया। लगभग एक महीने बाद दिल्ली सरकार ने भी 2 दिसंबर को पेट्रोल पर वैट घटाकर 8.52 रुपये प्रति लीटर कर दिया, जिससे पंप पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से नीचे आ गई। 2 नवंबर 2021 को दिल्ली में पेट्रोल 110.04 रुपये प्रति लीटर और डीजल 98.42 रुपये पर पहुंचा था। ये कीमतें सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं थीं। दो दिसंबर 2021 से 21 मार्च 2022 तक दिल्ली में पेट्रोल 95.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर था।

पेट्रोल-डीजल के दाम 9 दिन में 8वीं बार बढ़े

पेट्रोल-डीजल के दाम 9 दिन में 8वीं बार बढ़े। बुधवार को पेट्रोल-डीजल पर 80-80 पैसे बढ़े हैं। बता दें 4 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये टैक्स घटाकर जो राहत दी थी, उसका असर अब खत्म हो चुका है। अब 9 दिन में पेट्रोल 5.60 रुपये महंगा हो गया है। अक्टूबर 2021 में 13 राज्यों की 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले थे। इसके बाद पेट्रोल पर 5 रुपए टैक्स घटा था।

कच्चे तेल के दाम में 72% तक का उछाल

मार्च में यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए। नवंबर से मार्च तक कच्चे तेल के दाम में 72% तक का उछाल आया, लेकिन पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। 10 मार्च को आए चुनावी नतीजे के 12 दिन बाद दाम बढ़ने शुरू हुए, जबकि कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं। मंगलवार को कच्चा तेल 6.79% गिरावट के साथ 104.84 डॉलर/बैरल रहा। यह उच्चतम स्तर से 31% कम है।

GDP के मोर्चे पर आई बुरी खबर, रेटिंग एजेंसी इक्रा ने की 0.8 फीसदी की कटौती

नई दिल्ली। एजेंसी

घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने यूक्रेन संकट के कारण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को 0.8 प्रतिशत घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। ये आरबीआई के अनुमान से कम है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया है। हालांकि, केंद्रीय बैंक अप्रैल की शुरुआत में अगले वित्त वर्ष के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति पेश करेगा। इसमें वृद्धि दर के अनुमान पर फिर से विचार किया जाएगा।

क्या कहा गया: इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने जिंसों की कीमतों में उछाल और यूक्रेन में सैन्य संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला में बाधा को वृद्धि दर के अनुमान में कमी की प्रमुख वजह बताया है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वास्तविक वृद्धि तीन से चार प्रतिशत रह सकती है, जो तीसरी तिमाही के दौरान 5.4 प्रतिशत थी। इससे चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में वास्तविक वृद्धि दर के 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। नायर ने कहा, ''ईंधन और खाद्य तेलों जैसी वस्तुओं की ऊंची कीमतों से मध्यम से निम्न वर्ग की खर्च योग्य आय में कमी आ सकती है, जिससे वित्त वर्ष 2022-23 में मांग में पुनरुद्धार प्रभावित हो सकता है।'' उन्होंने मुफ्त अनाज योजना को सितंबर, 2022 तक बढ़ाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कमजोर वर्ग के लोगों को अपने खाद्यान्न बजट के मोर्चे पर कुछ राहत मिलेगी।

ONGC की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

तेल कंपनी की 1.5% हिस्सेदारी बेचकर 3000 करोड़ जुटाएगी सरकार, ऑफर फॉर सेल 30-31 मार्च तक खुलेगा

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के टॉप ऑयल और गैस प्रड्यूसर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में सरकार अपनी 1.5% हिस्सेदारी बेचकर करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। ध्ऊ ने मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इसके लिए ऑफर फॉर सेल (ध्इए) 30 और 31 मार्च को खुलेगा। लास्ट अवेलेबल शेयर होल्डिंग डेटा के अनुसार भारत सरकार की ओएनजीसी लिमिटेड में 60.41% हिस्सेदारी है।

31 मार्च को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सब्सक्रिप्शन

प्रपोज्ड ऑफर में 94,352,094 शेयर या 0.75% इक्विटी हिस्सेदारी का बेस ऑफर है। नॉन-रिटेल इन्वेस्टर्स 30 मार्च को इसे सब्सक्राइब कर पाएंगे। 31 मार्च को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सब्सक्रिप्शन रहेगा। ओवरसब्सक्रिप्शन होने पर इतनी ही एडिशनल इक्विटी बेचने का भी विकल्प है। इसका फ्लोर प्राइस 159 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। यह कीमत मंगलवार को ONGC के 171.05 रुपए के स्टॉक क्लोजिंग प्राइस से 7% डिस्काउंट पर है। निवेशक 159 रुपए के फ्लोर प्राइस पर या उससे ज्यादा प्राइस पर बोली लगा सकते हैं; या वे 'कट ऑफ' प्राइस पर भी बोली लगाने का विकल्प चुन सकते हैं। शेयरों का आवंटन OFS गाइडलाइन के अनुसार मल्टीपल क्लीयरिंग प्राइस के आधार पर होगा।

10% शेयर रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व

ओएफएस में, कम से कम 25% शेयर म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के लिए रिजर्व हैं जबकि 10% रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व हैं। रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख से ज्यादा शेयरों के लिए बोली नहीं लगा सकते। ONGC के कर्मचारी 5 लाख रुपए तक के इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्इए में बेचे जा रहे इक्विटी शेयरों का 0.075ज्ञ कट-ऑफ प्राइस पर एलिजिबल एम्पलॉइज के लिए है।

सरकार ने घटाया डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट

जनवरी 2022 तक, केंद्र सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड के जरिए लगभग 45,485.87 करोड़ रुपए जुटाए है। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए सरकार का रिवाइज्ड डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 78,000 करोड़ रुपए है। शुरूआत में इस टारगेट को 1.75 ट्रिलियन रुपए निर्धारित किया गया था।

खुशखबरी: 1 अप्रैल से यहां सीएनजी सस्ती हो जाएगी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली। एजेंसी

बढ़ती महंगाई के बीच मुंबई वालों को 1 अप्रैल से बड़ी राहत मिलने वाली है। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से सीएनजी सस्ती हो जाएगी। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने सीएनजी पर वैट की दरों में भारी कटौती करने का निर्णय किया है।

अभी 13.5 प्रतिशत वैट

बता दें कि महाराष्ट्र में अभी सीएनजी पर अभी 13.5 प्रतिशत वैट लगता है, जिसे महाराष्ट्र सरकार 1 अप्रैल से घटाकर 3 प्रतिशत कर रही है। गौरतलब है कि 11 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करते हुए महाराष्ट्र के वित्तमंत्री अजीत पवार ने इस बारे में ऐलान किया था।

वर्तमान में क्या है रेट

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और आसपास के एरिया में महानगर गैस सीएनजी गैस की सप्लाई करती है। मुंबई में अभी सीएनजी का रेट 66 रुपये प्रति किलोग्राम, जबकि पीएनजी का रेट 39.50 रुपये प्रति मानक घन मीटर है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में हाल ही में 50 पैसे का इजाफा किया गया है। दिल्ली में सीएनजी के दाम अब 57.51 रुपये प्रति किलो है। इसी तरह, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 1 रुपये बढ़ गई है। एनसीआर में ग्राहकों को 59.58 रुपये प्रति किलो सीएनजी मिल रहा है।

एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड ने 'द पार्क इंदौर' की लॉन्चिंग के साथ मध्य भारत में किया अपने कदमों का विस्तार

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड अपनी नई होटल 'द पार्क' इंदौर के साथ मध्यप्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल (वित्तीय राजधानी) में अपना विस्तार कर रहा हैं। द पार्क, इंदौर - जो कि आधुनिकता, विशिष्टता से भरपूर लेकिन विस्तृत और भव्य प्रांगण से सजा यह होटल बिजनेस और भ्रमण दोनों ही तरह के लिए यात्रा करने वाले अतिथियों के लिए लक्ज़री और आराम के अनुभव को एकदम सही अर्थों में परिभाषित करने वाला स्थान है। इंदौर के भव्य क्षेत्रों में से एक स्कीम नंबर 134 पर बसा और देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 99 कमरों का यह होटल मन को एकदम तरोताजा करने वाले कंटेम्परेरी डिजाइन्स से सुसज्जित है। यह होटल अतिथियों के भोजन, रहने, काम करने और अपनी खास खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए एक बेहतरीन, आनंददायक और रोमांचक और शानदार मंच प्रदान करता है। द पार्क, शहर में पहली बार अपने अग्रणी ब्रांड्स ऑरा, एक्वा, समप्लेस एल्स और फ्लरीज़ को लेकर आ रहे हैं।

ऑरा: स्पा और वेल बीइंग के विचार के साथ बनाई गई ये सुविधा ताजे स्थानीय इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करते हुए हाई क्वालिटी (उच्च गुणवत्ता) वाला स्वदेशी स्पा उपचार प्रदान करती है, साथ ही पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार की सेवाएं भी देती है।

होटल में म्यूजिक का 'मक्का'/ दिल माने जाने वाले 'समप्लेस एल्स' पर आप मधुर धुनों और पैरों को थिरकने पर मजबूर करने वाले संगीत का आनंद लेते हैं । यहाँ इसके साथ ही क्लासिक रॉक से लेकर ऊँश और रेयर माल्ट से लेकर रचनात्मकता के साथ बनाये गए कॉकटेल्स आपके समय को और आनंददायक बना देते हैं। यह पहली बार है जब द पार्क, कोल्कता वे अलावा किसी शहर में सम प्लेस एल्स को लेकर आ रहा है और वो शहर है आपका अपना इंदौर।

होटल इस बात को सुनिश्चित करता है कि आप इसके सदाबहार आइकॉनिक 'पटिसरीज़' (पेस्ट्रीज) का स्वाद लेने से वंचित न रहें। इसलिए आपके लिए यहाँ मौजूद है फ्लरीज़ जो मीठे के शौक़ीन लोगों के लिए ख़ास ट्रीट है। यहाँ के डिज़ट्र्स को आप न नहीं कह पाएंगे।

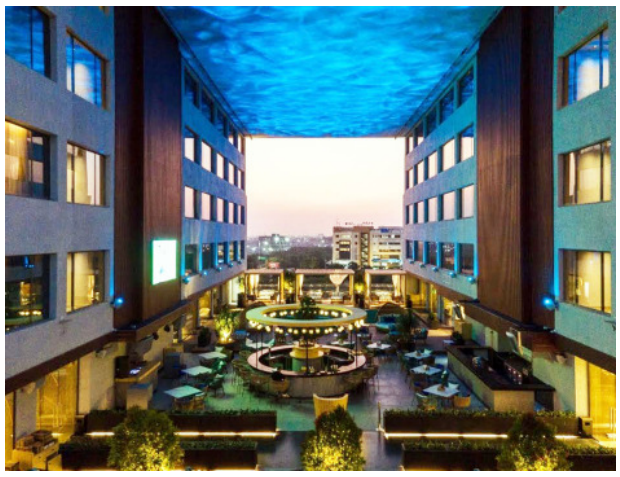

श्री देबजीत बैनर्जी, जनरल मैनेजर, द पार्क, इंदौर के अनुसार-'द पार्क, इंदौर का इंदौर में आगाज़ करते हुए हमें बहुत ख़ुशी हो रही है। हम अपने अतिथियों का स्वागत करने और उन्हें एक अद्भुत और नया अनुभव देने के लिए तैयार हैं। 2022 में कदम रखने के साथ ही एक निराशा भरे साल के बाद अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री (होटल उद्योग) के फिर से अपने कदमों पर खड़ा होने के दौर में, हम अपने अतिथियों को एक ख़ुशी और संतुष्टि से भरपूर स्थान उपलब्ध करवाने को लेकर रोमांचित हैं। यह होटल अपनी विशिष्ट सेवाओं के साथ ख़ास अनुभव देने और अतिथियों के लिए इस होटल को हमेशा की पसंद बनाने देने का वादा करता है।'

श्री विजय दीवान, मैनेजिंग डायरेक्टर, एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड ने इस अवसर पर कहा-'मध्य भारत के सबसे बड़े महानगर और साथ ही स्मार्ट सिटी में द पार्क को लांच करते हुए हम बेहद प्रसन्न हैं। हम अपने सबसे जीवंत बार और हैप्पिनिंग नाइटक्लब्स को इंदौर में लेकर आ रहे हैं। इसमें हमारे चार प्रमुख और अवॉर्ड विनिंग ब्रांड्स- ऑरा, एक्वा, समप्लेस एल्स और फ्लरीज़ शामिल हैं। हम यहाँ अपने कदमों का विस्तार करते हुए बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं। हम भविष्य में मध्य भारत क्षेत्र में और कई ओपनिंग्स और निरन्तर वृद्धि की पर देख रहे हैं।'

एडलवाइस ने मध्य प्रदेश में अपने ग्राहकों की संख्या 362% बढ़ाई

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एचएनआई (हाईनेट-वर्थ इंडिविजुअल्स) और समृद्ध ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने वाले, एडलवाइस वेल्थ मैनेजमेंट की वेल्थ मैनेजमेंट शाखा, एडलवाइस पर्सनल वेल्थ ने आज मध्य प्रदेश में अपने ग्राहक आधार में 362% की वृद्धि दर्ज करने घोषणा की। यह घोषणा ट्रेजर मॉल के पास, एडलवाइस की एम. जी. रोड स्थित इंदौर शाखा के उद्घाटन के अवसर पर की गई, जिसे अब डीएम टॉवर, 'रेसकोर्स रोड से स्थानांतरित' कर दिया गया है। नई शाखा इंदौर के बड़े ग्राहक आधार तक आसानी से पहुंच बनाना सुनिश्चित करेगी ताकि वे रिलेशनशिप मैनेजरों से मिल सकें और अपनी वित्तीय और सर्विसिंग जरूरतों के अनुकूल निवेश योजना को समझ सकें।

कंपनी की वृद्धि का कारण मुख्य रूप से अनुकूलित और निष्पक्ष अनुसंधान है, जिसमें यूजर्स के अनुकूल और उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के जरिये निवेशकों को दी गई सिफारिशें मददगार रही हैं। ये सिफारिशें वित्तीय बाजार में आसान निवेश और व्यापार को सक्षम करने के लिए कंपनी में ही तैयार की गई हैं।

एडलवाइस मोबाइल ट्रेडर (ईएमटी) एप्लिकेशन को 1 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। भारत के बाकी हिस्सों की तुलना में इसे इंदौर और मध्य प्रदेश में अधिक उपयोग किया गया है। ईएमटी एप्लिकेशन का लाभ उठाने वाले निवेशकों में भारत के 44ऊ की तुलना में इंदौर में वर्ष-दर-वर्ष 80ऊ और मध्य प्रदेश में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 65ऊ वृद्धि दर्ज की गई है। (इनहाउस मोबाइल ट्रेडर गूगल एनालिटिक्स के आधार पर)

उद्घाटन के अवसर पर श्री राहुल जैन, एडलवाइस, चेयरमैन एवं हेड, एडलवाइस, पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट ने कहा कि 'पिछले दशक में बचत के डिजिटलीकरण और वित्तीयकरण की वजह से धन प्रबंधन (वेल्थ मैनेजमेंट) में तेजी आई है। अब ईएमटी जैसे मोबाइल एप्लिकेशन तक पहुंच आसान होने के कारण निवेशक अलग-अलग प्रोफाइल के साथ ट्रेडिंग डोमेन में शामिल हो रहे हैं। परिणामस्वरूप पिछले 3 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में डीमैट खाते खोले गए हैं। निवेश के विभिन्न तरीकों की तलाश करने वाले ग्राहकों के साथ, मध्य प्रदेश के इंदौर में हमारे धन प्रबंधन व्यवसाय ने राज्य भर में बिजनेस और ग्राहक आधार में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, इसलिए हमें उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 23 में हम मध्य प्रदेश राज्य में अपने ग्राहक आधार में 500 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करेंगे।'

1 अप्रैल से आपकी जेब पर भारी पड़ेंगे ये 10 बदलाव

एलपीजी से लेकर दवाएं भी हो सकती हैं महंगी

नई दिल्ली। एजेंसी

नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी एक अप्रैल से कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर हर आम और खास की जेब पर पड़ने वाला है। एक तरफ पीएफ खाता और क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स चुकाना होगा। एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं। वहीं, होम लोन पर मिल रही अतिरिक्त छूट से हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा कई अन्य बदलाव भी होने जा रहे हैं, जो आपकी जेब पर बोझ बढ़ाएंगे। यहां हम आपको 10 ऐसे बदलावों के बारे बता रहें, जिसका असर आपके बजट पर पड़ सकता है।

1-पीएफ खाता पर टैक्स

एक अप्रैल 2022 से जो सबसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, उनमें सबसे अहम है पीएफ खाता पर टैक्स है। ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान की सीमा लगाई जा रही है। अगर इससे ऊपर योगदान किया, तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा पांच लाख रुपये सालाना होगी।

2-होम लोन पर अतिरिक्त छूट खत्म

सरकार ने 2019 के बजट में आयकर कानून में नया सेक्शन 80ईईए जोड़ा था। इस सेक्शन के तहत प्रावधान किया गया कि पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का फायदा दिया जाएगा। यह फायदा धारा 24 के अंतर्गत होम लोन के ब्याज पर अधिकतम दो लाख रुपये तक की टैक्स छूट के अतिरिक्त है। बजट 2022 में इस धारा को आगे के लिए नहीं बढ़ाया।

3-टैक्स के दायरे में क्रिप्टो से कमाई

एक बड़ा बदलाव क्रिप्टोकरंसी पर लगने वाले टैक्स का है। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया था। इसके तहत अगर क्रिप्टोकरंसी बेचने पर निवेशक को जो फायदा होगा उस पर उसे सरकार को टैक्स देना होगा। इसके साथ ही जब-जब कोई क्रिप्टोकरंसी बेचेगा तो उसकी बिक्री का एक फीसदी की दर से टीडीएस भी कटेगा।

4-दवाएं महंगी हो जाएंगी

नए वित्त वर्ष की शुरुआत से आम आदमी को दवाइयों पर खर्च बढ़ने वाला है। करीब 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी होने वाली है। इनमें बुखार की बुनियादी दवा पैरासिटामॉल भी शामिल है। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इन दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है।

5-डाकघर में नकद नहीं मिलेगा ब्याज

डाकघर की मासिक आय योजना (एमआईएस), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) या डाकघर टर्म डिपॉजिट में निवेश से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। इनमें ब्याज की राशि एक अप्रैल से नकद नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बचत खाता खोलना होगा। इसके अलावा जिन ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाता या बैंक खाता को अपनी इन योजनाओं से लिंक नहीं किया है उसे लिंक कराना जरूरी होगा। इसमें सीधे ब्याज का भुगतान होगा।

6-जीएसटी ई-चालान का नियम बदलेगा

सीबीआईसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर जीएसटी के तहत ई-चालान इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। यह नियम भी एक अप्रैल 2022 से लागू हो जा रहा है।

7-एक्सिस बैंक के ग्राहकों को झटका

एक्सिस बैंक में जिन ग्राहकों का वेतन अथवा बचत खाता है, उनके लिए नए नियम लागू हो रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दी है। एक्सिक बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने मुफ्त नकद निकासी की निर्धारित सीमा को भी बदलकर चार चार या 1.5 लाख रुपये कर दिया है।

8-म्यूचुअल फंड में केवल डिजिटल भुगतान

म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए एक अप्रैल से भुगतान, चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज एमएफयू 31 मार्च 2022 से चेक-डिमांड ड्राफ्ट आदि के जरिए पेमेंट सुविधा को बंद करने जा रहा है। इसके बाद राशि जमा करने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई या नेटबैंकिंग की सुविधा मिलेगी।

9- वाहन कंपनियां बढ़ाएंगी दाम

कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने वाहनों के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वह अपने वाणिज्यिक वाहनों की कीमतें 2.5 फीसदी तक बढ़ाएगी। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने भी कहा है कि वह वाहनों की कीमत तीन फीसदी तक बढ़ाएगी। टोयोटा कीमतों को चार फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। वहीं बीएमडब्ल्यू कीमतों में 3.5 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी।

10- एलपीजी के बढ़ सकते हैं दाम

चुनाव खत्म होने के बाद 12 दिन बाद 22 मार्च गए। एक बार फिर 1 अप्रैल को नए रेट जारी होंगे और पूरी आशंका है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 से 100 रुपये तक बढ़ जाएं। बता दें उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव के चलते एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में पिछले कई महीनों से राहत मिल रही थी। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 6 अक्टूबर 2021 को बदले थे।

सात पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई, राज्यों से 17 पीपीआर प्राप्त हुई : सरकार

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने बताया कि वर्ष 2027-28 तक 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय से 7 पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी गई है और इस संबंध में राज्य सरकारों से अब तक 17 परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) प्राप्त हुई हैं। लोकसभा में वस्त्र राज्यमंत्री दर्शना जरदोश ने पी रवींद्रनाथ के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्कों यानी पीएम मित्र पार्क की स्थापना के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है। मंत्री ने बताया, "सरकार ने वर्ष 2027-28 तक 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय से ग्रीन फील्ड/ब्राउनफील्ड क्षेत्रों में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 7 पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है।" दर्शना जरदोश ने बताया कि राज्य सरकारों से प्राप्त प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) के आधार पर पीएम मित्र पार्कों के लिए स्थानों के चयन का कार्य परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से अब तक 17 प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) प्राप्त हुई हैं। इनमें मध्य प्रदेश से चार, कर्नाटक से दो, आंध्र प्रदेश से एक, राजस्थान से एक, ओडिशा से एक, गुजरात से एक, तेलंगाना से एक, पंजाब से एक, छत्तीसगढ़ से एक, उत्तर प्रदेश से एक, बिहार से एक, तमिलनाडु से एक तथा महाराष्ट्र से एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

विदेश से खरीदे क्रिप्टो पर भी लग सकता है टैक्स

11 एक्सचेंज ने 81 करोड़ की जीएसटी चोरी की

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय एक्सचेंज की ओर से विदेश से खरीदे गए और भारत में खरीदी-बिक्री करने वाले क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स लग सकता है। इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कर विभाग इस बात की जांच कर रहा है भारत में ट्रेडिंग की अनुमति देने वाले एक्सचेंज अपनी क्रिप्टोकरंसी का प्रबंधन कैसे करते हैं और क्या कोई तत्व या लेनदेन है जहां वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हो सकता है। इस समय भारत में कई क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज संचालित हैं लेकिन इनमें

से बड़े एक्सचेंज के पास ही वास्तव में भारतीयों निवेशकों को बेचने और खरीदने के लिए अपनी किप्टोकरंसी उपलब्ध है। कुछ बड़े एक्सचेंज की भारत से बाहर भी शाखाएं हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में क्रिप्टो असेट्स हैं। यह एक्सचेंज बिक्री से पहले क्रिप्टो को भारतीय एंटिटी को हस्तांतरित करते हैं। देश के 11 क्रिप्टो एक्सचेंज ने संयुक्त रूप से 81.54 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में यह जानकारी दी है। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरण ने यह कर चोरी पकड़ी और जुर्माने के साथ 95.86 करोड़ रुपये वसूले हैं। जीएसटी चोरी करने वालों में कई नामी-गिरामी क्रिप्टो एक्सचेंज भी शामिल हैं।

वेबसाइट हैकिंग के मामलों में तेजी , पिछले तीन साल में 80 हजार वेबसाइट हैक

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में सरकारी प्रयासों के बाद भी वेबसाइट हैकिंग के मामलों में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी आकंड़ों के मुताबिक पिछले तीन सालों में देशभर में करीब 80 हजार वेबसाइट हैक की जा चुकी हैं। सरकार का दावा है कि इस समस्या से निपटने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय के आकंड़ों के मुताबिक, साल 2019 में 24,768, साल 2020 में 26,121 और साल 2021 के दौरान 28,897 भारतीय वेबसाइट हैक की गईं। देश में साइबर सुरक्षा की घटनाओं पर नजर रखने और निगरानी बनाए रखने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल यानि सर्ट-इन को अधिकृत किया गया है।

हैकिंग रोकने के सरकारी प्रयास

सर्ट-इन लगातार नए साइबर खतरों को लेकर लेकर सलाह जारी करता रहता है, जिससे वेबसाइट को हैक होने से बचाया जा सके। गृह मंत्रालय की तरफ से ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त चलाया जाता है, जिसमें समय-समय पर संभावित खतरों से आगाह किया जाता है। रिजर्व बैंक की तरफ से भी वित्तीय व्यवस्था को साइबर हमलों से बचाने के लिए एडवायजरी जारी की जाती रहती है।

होस्टिंग से पहले ऑडिट

सरकारी वेबसाइट को हैकिंग से बचाने के लिए उनका होस्टिंग से पहले साइबर सुरक्षा के संबंध में ऑडिट किया जाता है। होस्टिंग के बाद भी वेबसाइट और एप्लीकेशन का ऑडिट नियमित

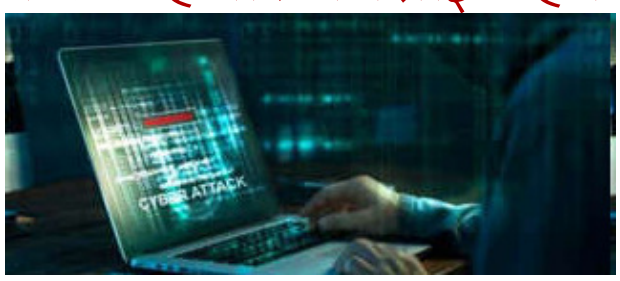

तौर पर किया जाता है। इसके लिए सर्ट इन की तरफ से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों व उनके महत्वपूर्ण संगठनों को साइबर हमले से मुकाबले के लिए साइबर संकट प्रबंध योजना भी तैयार की गई है।

तेल की कीमतों पर घमासान

वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार पर ठीकरा फोड़ा, ऑयल बॉन्ड को बताया जिम्मेदार

नयी दिल्ली। एजेंसी

तेल की कीमतों पर संसद में छिड़े घमासान के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के साथ पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने दो लाख करोड़ रुपये के ऑयल बांड इशू किए थे, जिसके चलते तेल की कीमतें कम करना संभव नहीं हो पा रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच जहां ब्रेंट क्रूड की कीमतें आसमान पर है, तो दूसरी ओर देश में भी तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। हालात ये हैं कि बीते नौ दिन में आठ बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। बुधवार को एक बार इनके दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई। तेल की इन बढ़ती कीमतों को लेकर जहां आम जनता परेशान है, तो संसद में भी इस मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये रोज की बात है, तो मंगलवार को वित्त मंत्री ने इसके लिए कांग्रेस की यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

मुंबई में सबसे महंगा पेट्रोल

पहले बात कर लें तेल की ताजा कीमतों की। तो बता दें कि आठ बार की बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 101.01 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 92.27 रुपये प्रति लीटर हो गया। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115.88 रुपये व डीजल की कीमत 100.10 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके अलावा मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ऐसे राज्य हैं जहां पर पेट्रोल का भाव 100 रुपये पर बना हुआ है। बीते चार नवंबर 2021 को केंद्र ने पांच महीने के बाद उत्पाद शुल्क में पांच रुपये की कटौती कर जनता को राहत दी थी, लेकिन बीते नौ दिनों में ही पेट्रोल 5.60 रुपये महंगा हो चुका है।

राहुल का वार, सीतारमण का पलटवार

रोजाना बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी के रोज के कामों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही महंगाई को लेकर हैशटैग रोज सुबह की बात भी लिखी है। तेल की कीमतों पर छिड़े इस घमासान के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री ने सरकार का बचाव करते हुए मंगलवार को संसद में कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अंकुश ना लग पाने के पीछे पूर्व कांग्रेस सरकार है। उन्होंने एक बार फिर से ऑयल बांड का जिक्र किया। सीतारमण ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि देश में तेल की आसमान छूती कीमतों के लिए अन्य बातों के अलावा ऑयल बांड भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने दो लाख करोड़ रुपये के ऑयल बांड इशू किए थे, जिसके चलते तेल की कीमतें कम करना संभव नहीं हो पा रहा है।

2026 तक चलेगा ये सिलसिला

राज्यसभा में मंगलवार को वित्त विधेयक एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच एक महीने से ज्यादा समय से जारी भीषण जंग का असर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आज लोग जो इन ईंधनों का महंगा दाम चुका रहे हैं, वह एक दशक पहले दी गई सब्सिडी के कारण है। उस समय ऑयल बांड के नाम पर दो लाख करोड़ रुपये लिए गए थे और इसका भुगतान जारी है जो कि साल 2026 तक चलेगा।

कच्चे तेल के दामों में आज भी तेजी

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बुधवार को भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। खबर लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड का दाम बढ़कर 112.78 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुका था। नायमैक्स क्रूड1.02 डॉलर यानी 0.98 फीसदी की तेजी के बाद 105.26 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। भारत पर भी कच्चे तेल के दामों की तेजी का असर देखा जा रहा है और यहां लगातार ईंधन के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है। पूर्व में जारी की गई रिपोर्ट को देखें तो अभी देश में तेल की कीमतों पर लगाम लगना संभव नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया था कि पेट्रोल और डभ्जल के दाम में क्रमशः 15 से 22 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

देश में बढ़ रहा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन

यूपीआई ट्रांजेक्शन चार साल में दोगुना हुआ, बैंकों की फी इनकम एक तिहाई घट गई

नयी दिल्ली। एजेंसी

यूपीआई ने देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया और डिजिटल लेनदेन आसान बना दिया। इसके चलते बीते चार साल में वैल्यू के हिसाब से रिटेल डिजिटल पेमेंट में यूपीआई की हिस्सेदारी दोगुनी से ज्यादा हो गई; लेकिन बैंकों, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों की फी इनकम करीब एक तिहाई घट गई। इन्हें यूपीआई ट्रांजेक्शन से आय नहीं होती है। दरअसल, मुफ्त और आसान सर्विस के चलते यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का इस्तेमाल साल दर साल तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीनों में ही पर्सन-टू-मर्चेंट पेमेंट्स में यूपीआई की हिस्सेदारी 42ज्ञ हो गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 28ज्ञ थी। स्थिति यह है कि वैल्यू के हिसाब से फरवरी में करीब 80ज्ञ रिटेल डिजिटल पेमेंट यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिये हुए। आईएमपीएस और नेफ्ट जैसे तरीकों से लेनदेन इसमें शामिल नहीं है।

बैंकों की फी इनकम घटी

विश्लेषकों के मुताबिक, यूपीआई ट्रांजेक्शन बढ़ने से बैंकों की फी इनकम घटी है। मसलन, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एक्सिस बैंक की कुल फी इनकम में रिटेल कार्ड फी के तौर पर होने वाली आय घटकर 1.9ज्ञ रह गई जो चार साल पहले 2.5ज्ञ थी। अन्य बैंकों की भी मोटे तौर पर यही स्थिति है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने एक नोट में लिखा है, 'पेमेंट प्रोसेसिंग बिजनेस में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन बढ़ने की वजह से पूरे इकोसिस्टम में पेमेंट्स फी के तौर पर होने वाली आय लगातार घटती जा रही है।'

एमडीआर पेमेंट पूल में बैंकों की हिस्सेदारी बड़ी, नुकसान भी ज्यादा

दरअसल एमडीआर पेमेंट पूल में बैंकों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है क्योंकि ज्यादातर कार्ड बैंक ही जारी करते हैं। बैंक कार्ड-आधारित पेमेंट और अन्य डिजिटल ट्रांजेक्शंस के लिए तो मर्चेंट से शुल्क वसूल सकते हैं, लेकिन यूपीआई पेमेंट के लिए शुल्क नहीं ले सकते।

कैशलेस को बढ़ावा देने 2019 से मुफ्त हुए यूपीआई ट्रांजेक्शन

सरकार ने 2019 में यूपीआई ट्रांजेक्शन के मामले में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शून्य कर दिया था, ताकि देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके। इससे पहले हर डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए मर्चेंट्स को पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को एमडीआर चुकाना होता था।

आरबीआई का दावा : बैंकिंग धोखाधड़ी से रोज 100 करोड़ की चपत

सिर्फ 5 राज्यों में 83 फीसदी मामले, दिल्ली दूसरे स्थान पर

मुंबई। एजेंसी

धोखाधड़ी की ज्यादातर घटनाएं उधारी देने में ही होती हैं। ऐसे मामलों में या तो नियमों से ज्यादा कर्ज दिया जाता है या जमानत नहीं रखी जाती है। अमेरिका में हर दिन उधारी से जुड़े मामलों में असेसमेंट होता है, जो भारतीय बैंकों में नहीं किया जाता है। इसके लिए बैंकों को विशेष टीम गठित करनी चाहिए।

देश को बैंक धोखाधड़ी की वजह से पिछले सात वर्षों में हर रोज 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि, नुकसान की इस रकम में साल-दर-साल गिरावट आ रही है। आरबीआई के मुताबिक, देश में बैंकिंग धोखाधड़ी के 83 फीसदी मामले केवल पांच राज्यों में हैं। इसमें 50 फीसदी के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है, जबकि दिल्ली दूसरे स्थान पर है। उसके बाद सबसे ज्यादा बैंकिंग धोखाधड़ी तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में है।

आंकड़ों के मुताबिक, एक अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2021 तक सभी राज्यों में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की बैंकिंग धोखाधड़ी हुई। इनमें इन पांच राज्यों की हिस्सेदारी दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा यानी 83ज्ञ है। आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी को आठ वर्गों में बांटा है। हालांकि, वित्त मंत्रालय का कहना है कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग और रोकथाम के लिए कदम उठाए गए हैं। इससे बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में हर साल कमी आ रही है।

नियमों को ताक पर रखकर उधारी देने में बढ़े मामले

धोखाधड़ी की ज्यादातर घटनाएं उधारी देने में ही होती हैं। ऐसे मामलों में या तो नियमों से ज्यादा कर्ज दिया जाता है या जमानत नहीं रखी जाती है। अमेरिका में हर दिन उधारी से जुड़े मामलों में असेसमेंट होता है, जो भारतीय बैंकों में नहीं किया जाता है। इसके लिए बैंकों को विशेष टीम गठित करनी चाहिए। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष वाई सुदर्शन का कहना है कि हाल में बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी इसलिए आई है क्योंकि बैंक और सरकार मिलकर कदम उठा रहे हैं। बाहरी धोखाधड़ी से बचने के लिए बैंक काफी प्रयास करते हैं, पर उन्हें चाहिए कि वे अपने कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार बनाएं। खासकर ऐसे मामलों में, जहां ज्यादा उधारी दी जाती है।

शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 740 अंक उछलकर बंद, निफ्टी 147 अंक चढ़ा

मुंबई। एजेंसी

सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई और दिनभर दोनों सूचकांक हरे निशान पर कारोबार करते रहे। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 740 अंक या 1.28 फीसदी की उछाल के साथ 58,684 के स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक भी 147 अंक या 0.85 फीसदी की तेजी लेते हुए 17,472 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले बीएसई का सेंसेक्स 343 अंक की तेजी लेते हुए 58,286 के

स्तर पर खुला था, जबकि एनएसई के निफ्टी सूचकांक ने 90 अंकों की उछाल के साथ 15,400 के पार कारोबार की शुरुआत की थी। निफ्टी 17,415 के स्तर पर खुला। बाजार की शुरुआत में 1591 शेयर बढ़त में खुले, वहीं 417 में गिरावट देखने को मिली थी। दिन बढ़ने के साथ दोनों सूचकांकों में तेजी बढ़ती गई और अंत में तेज बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। गौरतलब है कि बीते कारोबारी सत्र में मंगलवार को सेंसेक्स 350 अंक या 0.61 फीसदी की उछाल के साथ 57,944 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 103 अंक की तेजी लेते हुए 17,325 के स्तर पर बंद हुआ था।

चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से:1563 साल बाद दुर्लभ संयोग में शुरू होगा हिंदू नव वर्ष, सुख-सम्पत्ति बढ़ाने वाले 3 राजयोग में शुरू होगी नवरात्रि

2 अप्रैल शनिवार से हिंदू पंचांग का नवसंवत् 2079 शुरू हो रहा है। इसका नाम नल है और राजा शनि देव रहेंगे। शनिवार को ही चैत्र नवरात्र शुरू हो जाएंगे, जो 10 अप्रैल, रविवार तक रहेंगे। इस बार रेवती नक्षत्र और तीन राजयोगों में नववर्ष की शुरुआत होना शुभ संकेत है। साथ ही नवरात्र में तिथि की घट-बढ़ नहीं होने से देवी पर्व पूरे 9 दिन का रहेगा। इस तरह अखंड नवरात्र सुख-समृद्धि देने वाली रहेगी।

1563 साल बाद अति दुर्लभ संयोग

ज्योतिषाचार्य पं. प्रफुल्ल भट्ट के मुताबिक, इस साल नववर्ष की शुरुआत में मंगल और राहु-केतु अपनी उच्च राशि में रहेंगे वहीं, शनि खुद की ही राशि मकर में होगा। नववर्ष के सूर्योदय की कुंडली में शनि-मंगल की युति से धन, भाग्य और लाभ का शुभ योग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से ये साल मिथुन, तुला और धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। वहीं, अन्य राशियों के लिए बड़े बदलाव का समय रहेगा। ग्रहों का ऐसा संयोग 1563 साल बाद बन रहा है। इससे पहले 22 मार्च 459 को ये ग्रह स्थिति बनी थी।

पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉ. गणेश मिश्र के मुताबिक, ये नववर्ष रेवती नक्षत्र में शुरू होगा। इसके स्वामी बुध हैं। बुध के कारण कारोबार में फायदा होता है, इसलिए इस नक्षत्र में खरीद-बिक्री करना शुभ माना जाता है। व्यापार का कारक बुध भी इस नक्षत्र में रहेगा। इससे बड़े लेन-देन और निवेश के लिए पूरा साल शुभ रहेगा।

आर्थिक मजबूती और व्यापार को बढ़ाने वाला साल

इस बार सरल, सत्कीर्ति और वेशि नाम के राजयोगों में नववर्ष की शुरुआत हो रही है, जिससे नवरात्र में खरीदारी, लेन-देन, निवेश और नए कामों की शुरुआत करना शुभ रहेगा। इन योगों का शुभ फल पूरे साल दिखेगा। इस कारण कई लोगों के लिए ये साल सफलता और आर्थिक मजबूती देने वाला रहेगा। इस साल लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनेंगी और उन पर काम भी होगा। कई लोगों के लिए बड़े बदलाव वाला साल रहेगा।

शनि राजा और गुरु मंत्री

काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रो. रामनारायण द्विवेदी बताते हैं कि इस संवत्सर में ग्रहों के खगोलीय मन्त्री परिषद के 10 विभागों में राजा और मंत्री सहित 5 विभाग पाप ग्रहों के पास तथा 5 शुभ ग्रहों के पास रहेगा। इस वर्ष राजा-शनि, मन्त्री-गुरु, सस्येश-सूर्य, दुर्गेश-बुध, धनेश-शनि, रसेश-मंगल, धान्येश-शुक्र, नीरसेश-शनि, फलेश-बुध, मेघेश-बुध होंगे। नवसंवत्सर 2079 में राजा शनि देव व मंत्री देव गुरु बृहस्पति रहेंगे। ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव कर्म फल से न्याय प्रदान करेंगे, वहीं देव गुरु बृहस्पति मंत्री के रूप में सकारात्मकता बढ़ाएंगे। जब शनि वर्ष के राजा होते हैं तो देश में उत्पात और अव्यवस्था तो बढ़ती है, लेकिन मंत्री गुरु होने से विद्वानों की अच्छी सलाह से मुसीबतें कम हो जाती हैं। इस दौरान धार्मिक कार्य बढ़ेंगे। शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा।

नववर्ष शुरू होते ही 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन

नववर्ष के शुरू होते ही सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अप्रैल में सबसे पहले मंगल 7 तारीख को मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। इसके अगले दिन बुध मेष राशि में आ जाएगा। फिर 11 अप्रैल को राहु-केतु राशि बदलकर मेष और तुला में आ जाएंगे। 13 को गुरु कुंभ राशि में और 14 को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में आएगा। इसके बाद महीने के आखिरी में 27 को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में और 28 को शनि अपनी ही राशि कुंभ में प्रवेश करेगा। चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि बदलता ही है। इस तरह नए साल के शुरू होने के महीने भर में ही सारे 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर लेंगे।

इस दिन मनाई जाएगी राम नवमी, जानिए पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

राम नवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में राम नवमी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन राजा दशरथ के घर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस दिन विधि-विधान से भगवान श्रीराम की पूजा की जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 02 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। जानिए किस दिन मनाई जाएगी रामनवमी और भगवान श्री राम की पूजा का समय-

राम नवमी 2022 तिथि और शुभ मुहूर्त

रामनवमी इस साल 10 अप्रैल 2022, रविवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि 10 अप्रैल को प्रातः 01.32 बजे से प्रारंभ होकर 11 अप्रैल को प्रातः 03.15 बजे समाप्त होगी। भगवान श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त 10 अप्रैल 2022 को प्रातः 11.10 बजे से 01.32 बजे तक रहेगा।

राम नवमी पूजा विधि

रामनवमी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद रोली से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियों का तिलक करें, फिर भगवान श्री राम को चावल, फूल, घंटी और शंख चढ़ाकर भगवान श्री राम की विधिवत पूजा करें। श्री राम के मंत्रों का जाप करें, रामायण का पाठ करें और रामचरितमानस का भी पाठ करें। अंत में सभी की आरती करें। इस दिन भगवान श्री राम को झूला झूलना चाहिए और किसी गरीब या ब्राह्मण को गेहूं और बाजरा दान करना चाहिए।

राम नवमी 2022 का महत्व

भगवान राम ने अपना चौदह वर्ष का वनवास किया और इस दौरान उन्होंने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से जीवन में हर तरह की सुख-समृद्धि आती है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। यह भी एक कारण है कि इस बार भगवान राम के प्रति भक्ति का भाव विशेष दर्जे का होगा।

चैत्र नवरात्रि में जरूर करें ये वास्तु उपाय, सुख समृद्धि से भर जाएगा घर परिवार

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होने वाली है और देशभर में देवी मां की भक्त घटस्थापना की तैयारियों में जुट गए हैं। नवरात्रि के नौ दिन वास्तु के साथ-साथ मां दुर्गा के व्रत-पूजा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप भी चैत्र नवरात्रि के दौरान घटस्थापना कर रहे हैं तो कुछ वास्तु उपायों का ध्यान जरूर दें। गौरतलब है कि चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 से शुरू होगी, जो 11 अप्रैल 2022 तक चलेगी।

चैत्र नवरात्रि में करें ये वास्तु उपाय

■ चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कलश की स्थापना ईशान कोण में करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में ईशान कोण को सबसे शुभ और पूजा के लिए उत्तम माना गया है। ऐसा करने से परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ती है।

■ नवरात्रि में मां दुर्गा की अखंड ज्योति को आग्नेय दिशा यानी दक्षिण-पूर्व कोण की दिशा में रखें। वास्तु के मुताबिक ऐसा करने से घर के दोष दूर हो जाते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य का रोग दूर होता हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है।

■ चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान रोज मुख्य द्वार पर अंदर की ओर आने वाली देवी लक्ष्मी के पैर बनाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से ऐश्वर्य और वैभव की वृद्धि होती है।

■ नवरात्रि के दौरान व्यापारियों को अपने कार्यालय दुकान के मुख्य द्वार पर एक बर्तन में पानी भरकर पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। लाल और पीले फूल भी जल में डालें। व्यापार में उन्नति होती है।

■ घर में ही कन्या पूजन करें और कन्याओं को सम्मान से भोजन कराएं और उनकी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दें। ऐसा करने से घर से वास्तु दोष दूर होता है।

12 अप्रैल तक इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क, बुध अस्त से जीवन में आएंगी एक के बाद एक मुश्किलें

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका मानव जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में ग्रहों के राजकुमार बुध अस्त हैं। बुधदेव 14 मार्च 2022, सोमवार को सुबह 05 बजकर 53 मिनट पर अस्त हुए थे और 12 अप्रैल 2022, मंगलवार को शाम 07 बजकर 32 मिनट पर उदित होंगे। इस दौरान बुध कुल 30 दिनों के लिए अस्त रहेंगे। जानें बुध अस्त का किन राशि वालों पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव-

मेष- बुध आपकी राशि के 11वें भाव में अस्त हुए हैं। जिसे आय व लाभ का भाव कहा जाता है। इसलिए आपको नौकरी व व्यापार में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आय के साधनों में कमी आ सकती है। व्यापारियों की कोई डील फाइनल होते-होते रूक सकती है। फिलहाल पैसों के निवेश में सावधानी बरतें की जरूरत है।

वृषभ- आपकी राशि के लिए बुध का अस्त होना कष्टकारी साबित हो सकता है। बुध आपके जॉब व करियर भाव में अस्त हुए हैं। जिसके कारण आपको नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में मिलने वाले अवसर छूट सकते हैं। कार्यक्षेत्र में काम का दवाब अधिक होगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको मेहनत का फल नहीं मिलने की आशंका है।

मिथुन- बुध आपकी राशि के नवम स्थान में अस्त हुए हैं। नवम भाव को भाग्य व विदेश स्थान माना गया है। बुध अस्त के प्रभाव से आपको 12 अप्रैल तक किस्मत का कम साथ मिलेगा। आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। बुध अस्त काल में आपको दस्तावेज संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में कोई डील फाइनल होते-होते रूक सकती है। कार्यस्थल पर सहकर्मचारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं।

डीएसपी इनवेस्टमेंट मैनेजर्स ने डीएसपी निफ्टी एसडीएल प्लस जी-सेक जून 2028 30:70 इंडेक्स फंड लॉन्च किया

यह फंड स्थिर और अनुमानित रिटर्न की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए है

मुंबई। एजेंसी

डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने डीएसपी निफ्टी एसडीएल प्लस जी - सेक जून 2028 30:70 इंडेक्स फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक खुली अवधि का टार्गेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है, जो छह साल बाद जून 2028 में परिपक्व होगा। पोर्टफोलियो की पूंजी केवल सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के बीच 70:30 अनुपात में निवेश की जाएगी, जो निफ्टी एसडीएल प्लस जी - सेक जून 2028 30:70 इंडेक्स के अनुरूप है। एसडीएल के चयन के लिए पोर्टफोलियो को दोहरे फिल्टर के साथ अनूठे तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें लिक्विडिटी फिल्टर के साथ कम लाभ वाले अतिरिक्त गुणवत्ता फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है। यह गुणवत्ता फिल्टर प्रत्येक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर उसकी कुल देनदारियों के अनुपात में आधारित है और सर्वोत्तम गुणवत्ता स्कोर वाले शीर्ष 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का चयन किया जाएगा। इसलिए पोर्टफोलियो में अत्यधिक तरल सरकारी प्रतिभूतियां और कम समर्थन व उच्च तरलता वाले एसडीएल की एक चुनिंदा सूची होगी, जो सभी 30 जून, 2028 को समाप्त 12 महीने की अवधि के दौरान परिपक्व हो रहे हैं। यह फंड निवेशकों को अपेक्षाकृत स्थिर और अनुमानित रिटर्न की क्षमता प्रदान करता है। 31 मार्च 2022 से पहले निवेश करने पर दीर्घकालिक निवेशकों (तीन साल से अधिक की होल्डिंग वाले) को भी इंडेक्सेशन लाभ के मामले में अतिरिक्त साल का लाभ मिल सकता है। जो निवेशक एनएफओ के दौरान सब्सक्राइब करते हैं और इसके परिपक?व होने तक इसमें निवेश के साथ बने रहते हैं, उन्हें कुल 7 साल का इंडेक्सेशन लाभ मिल सकता है। डीएसपी इनवेस्टमेंट मैनेजर्स में पैसिव इनवेस्टमेंट्स एंड प्रॉडक्ट्स के प्रमुख और सीएफए अनिल घेलानी ने कहा,'डीएसपी निफ्टी एसडीएल प्लस जी - सेक जून 2028 30:70 इंडेक्स फंड में अनूठे गुणवत्ता फ़िल्टर के साथ आता है, जो सबसे कम ऋण / जीडीपी वाले शीर्ष 10 राज्यों को उनकी वित्त (वित्तीय) स्थिति के आधार पर चुनता है। महामारी के बाद के वर्षों में, जहां राज्यों की राजकोषीय स्थिति अधिक भेदभावपूर्ण हो जाएगी, इसलिए निवेश करने से पहले राज्यों के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है।'' डीएसपी इनवेस्टमेंट मैनेजर्स में फिक्स्ड इनकम के प्रमुख संदीप यादव ने कहा, 'फंड में निवेश का सत्तर (70) प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में है। जी-सेक और एसडीएल के बीच आवंटन अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। ऐसे कम विभाजन पर सरकारी प्रतिभूतियों के अपेक्षाकृत सुरक्षित जोखिम प्रोफाइल को देखते हुए, एसडीएल की तुलना में सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक निवेश करना समझ में आता है। साथ ही हमारा मानना है कि यील्ड ग्राफ की वृद्धि 2028 तक तेज है, और उसके बाद इसकी वृद्धि अपेक्षाकृत कम है। चूंकि वार्षिक प्रसार 2028 तक बढ़ता है और फिर यह समतल हो जाता है, इसलिए छह साल का बिंदु एक अनुमानित पैसिव रणनीति के लिए आकर्षक बिंदु है।'

गूगल क्लाउड के साथ रणनीतिक तौर पर डिजिटल ट्रांसफ़ार्मेशन को बढ़ावा देगा अदाणी समूह

यह संगठन भविष्य के मापदंडों को देखते हुए अदाणी के आईटी ऑपरेशन को आधुनिक बनाने और समूह-व्यापी इनोवेशन को संचालित करने के लिए साथ आए हैं।

अहमदाबाद। एजेंसी

अदाणी समूह ने आज भारत के सबसे तेजी से बढ़ते डायवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो में इनोवेशन के अगले चरण को शक्ति प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ एक बहु-वर्षीय, क्लाउड-फर्स्ट पार्टनरशिप की घोषणा की है। यह रणनीतिक साझेदारी खासकर, अदाणी ग्रुप के आईटी ऑपरेशंस को बड़े स्तर पर आधुनिक बनाने के लिए बेस्ट-इन-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री सॉल्यूशंस के मामले में प्रत्येक संगठन की विशेषज्ञता का उपयोग करेगी। अदाणी ग्रुप के चेयरमैन श्री गौतम अदाणी ने कहा, 'क्लाउड एडॉप्शन की अनिवार्यता और तेजी यह सुनिश्चित करती है कि हर एक व्यवसाय अपने बिजनेस मॉडल को फिर से परिभाषित करें। ये नई चुनौतियां और नए अवसर देता है जो न केवल परिवर्तनकारी होंगे बल्कि इंडस्ट्री कॉलेबोरेशन के नए रूपों की भी आवश्यकता होंगे। हमें एक प्रौद्योगिकी-संचालित संगठन बनाने में मदद करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ उसके बहुआयामी प्रस्तावों पर काम करते हुए खुशी महसूस हो रही है जो संभवतः हमारे लिए नए व्यावसायिक क्षेत्रों को खोलता है।' इस पार्टनरशिप का पहला दौर अच्छी तरह जारी है, अदाणी समूह अपने मौजूदा ऑन-प्रिमाइसेस डेटा सेंटर और कॉलोकेशन सुविधाओं से गूगल क्लाउड में अपने विशाल आईटी फुटप्रिंट्स माइग्रेट करने में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

अदाणी ग्रुप के 250+ बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस, जैसे कि इसके एसएपी हाना कोर और पेरिफेरल सिस्टम को गूगल क्लाउड के सुरक्षित, विश्वसनीय और हाई स्पीड वाले क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में स्थानांतरित करने से वर्कफ़्लो को सेंट्रलाइज किया जाएगा, संचालन को सुव्यवस्थित किया जाएगा और बिजनेस यूजर्स को तेजी से शक्तिशाली नए डेटा क्षमताओं को हासिल करने तथा सटीक निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाएगा।

गूगल क्लाउड के सीईओ श्री थॉमस कुरियन ने कहा, 'अदाणी ग्रुप क्लाउड-फर्स्ट भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त कर रहा है, और हम कंपनी के साथ ऐतिहासिक परियोजनाओं पर साझेदारी करने के लिए उत्साहित हैं जो इसके इनोवेशन और भविष्य के विकास में सहयोग करेगी। अदाणी का एसएपी माइग्रेशन सबसे तेज़ है जिसे हमने बड़े पैमाने पर देखा है और ये पहले से ही अपने व्यवसाय में महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान कर रहा है। हमारा निरंतर सहयोग नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नेतृत्व करेगा जिसका परिवर्तनकारी प्रभाव होगा।'

किर्लोस्कर मोटर्स ने 'हाई-एफिशिएंसी लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक मोटर्स' लॉन्च किया

पुणे। इंजन, इलेक्ट्रिक जेनरेटिंग सेट और खेती के औजार एवं उपकरण बनाने वाली अग्रणी कंपनी, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड (केओईएल), कई दशकों से पूरे विश्व के लोगों की जिन्दगी को बदलने में मददगार रही है। नए उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च करके ग्राहकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाने वाले अपने नजरिये के साथ, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड ने गर्व से उच्च दक्षता एवं कम वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिक मोटर्स लॉन्च किया, जो सभी उद्योगों में सभी एप्लिकेशंस में मशीनों को पावर प्रदान करेगा।

हाई परफॉरमेंस और एफिशिएंसी को सुनिश्चित करने के लिए, इन मोटरों का निर्माण उच्च ग्रेड तांबे के तारों से किया जाता है और इनका परीक्षण बीआईएस-अनुमोदित, एनएबीएल-मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला में होता है। बेहतर सेल्स एवं सर्विस नेटवर्क की मदद से क्वालिटी प्रोडक्ट्स की एक रेंज के साथ, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स ने 'उम्मीदों से परे प्रदर्शन' के मिशन के साथ काम किया है और इलेक्ट्रिक मोटर्स बाजार में शानदार उपस्थिति दर्ज की है। इस अवसर पर बोलते हुए, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड के एक्जिक्यूटिव चेयरमैन, श्री अतुल किर्लोस्कर ने कहा कि 'हमने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स एवं सॉल्यूशंस दिए हैं, जो हमारे ग्राहकों को संतुष्ट करते हैं और लागत बचाने में उनकी मदद करते हैं। इस परंपरा को जारी रखते हुए, हम किर्लोस्कर मोटर्स की अपनी नई रेंज पेश करने के लिए उत्साहित हैं। हम आज के लॉन्च को मौजूदा डीलरों और अपने ग्राहकों के अपने विशाल नेटवर्क को समर्पित करते हैं जो इस कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम नई विस्तार योजनाएं चला रहे हैं, मजबूत आरएंडडी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और नए बाजारों में कदम रख रहे हैं। मोटरों की हमारी नई रेंज बेस्ट-इन-क्लास परफॉरमेंस करेगी और हाई एफिशिएंसीके कारण बिजली की खपत भी कम करेगी।'

इस अवसर पर किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड की डायरेक्टर गौरी किर्लोस्कर ने कहाकि 'हमने जो लगातार सक्रिय योजना एवं रणनीतिक उपायों को अपनाया है, उसने हमें इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के क्षेत्र में एक मान्यताप्राप्त प्रोवाइडर बनाया है। किर्लोस्कर ने डीजल इंजन के क्षेत्र में स्वयं को एक प्रमुख कंपनी के रूप में स्थापित किया है, जिससे इलेक्ट्रिक मोटर्स के क्षेत्र में हमारा योगदान बढ़ेगा और इस सेगमेंट में भी हमारी उपस्थिति बनेगी। उन्होंने आगे कहाकि 'इन मोटरों में कोई दोष नहीं हैं और ये उच्चतम स्तर की विश्वसनीयता, सहनशक्ति और दक्षता सुनिश्चित करते हैं।' इस मोटर रेंज की शुरुआत करके किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स ने अपने व्यापक व्यावसायिक नजरिये के अनुरूप, नए उत्पाद प्रदान करने की अपनी पहल की पुष्टि की है।

मुफ्त राशनः देश के गरीबों का पेट भरने के लिए खर्च हो जाएंगे 3.40 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित कुल 39.45 लाख करोड़ रुपये के बजट का 5.2 फीसदी हिस्सा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रमों पर खर्च होगा। वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने 2.06 लाख करोड़ रुपये का बजट खाद्य सब्सिडी के लिए आवंटित किया था। गरीबों का पेट भरने के लिए चल रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को छह महीने का विस्तार देने के बाद इस मद में खर्च की कुल रकम 3.40 लाख करोड़ के पार होने का अनुमान है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान मुहैया कराती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की इसमें अहम भूमिका है।

वित्त वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड खर्च

केंद्र की भाजपा सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए कुल 1,15,570 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। हालांकि इस दौरान खाद्य सब्सिडी पर खर्च हुई रकम का आंकड़ा 4,22618 करोड़ के पार हो गया था। आवंटन की तुलना में खर्च हुई राशि में 366 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बीते दस वर्षों में ये सर्वाधिक बढ़ोतरी है।

जंग की आंच में खौलता रहेगा खाने का तेल

भारत ने रूस से रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा सूरजमुखी तेल

नई दिल्ली। एजेंसी

रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के कारण पहले ही खाद्य तेलों के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत ने रूस से रिकॉर्ड कीमत पर सूरजमुखी के तेल के आयात के लिए सौदा किया है। भारत में यूक्रेन से सबसे ज्यादा सूरजमुखी तेल का आयात करता है लेकिन लड़ाई के कारण वहां से आयात प्रभावित हुआ है। इस वजह से देश में खाद्य तेल की कीमतों में तेजी आई है। भारत ने अप्रैल में 45,000 टन सूर्यमुखी के तेल के लिए रूस के साथ डील की है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। भारत दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक है और रूस से मिलने वाले सनफ्लावर ऑयल से देश में इसकी कमी को पूरा किया जा सकेगा। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल की सप्लाई को सीमित कर दिया है जबकि दक्षिण अमेरिका में सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है। जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप चौधरी ने कहा कि यूक्रेन से आयात संभव नहीं है, इसलिए

खरीदार रूस का रुख कर रहे हैं। उनकी कंपनी ने रूस से 12,000 टन सूर्यमुखी तेल के आयात के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है।

रूस से रिकॉर्ड कीमत पर खरीद

डीलरों का कहना है कि रिफाइनर्स ने रूस से 2,150 डॉलर प्रति टन की रिकॉर्ड कीमत पर क्रूड सनफ्लावर ऑयल खरीदा है। इसमें कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट (ण्ष्ह) शामिल है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले यह कीमत 1,630 डॉलर प्रति टन थी। इस समय देश में सूरजमुखी के तेल की खुदरा कीमत 160 से 180 रुपए प्रति लीटर है। नई खेप आने के बाद इसमें 30 फीसदी तक तेजी आ सकती है यानी इसकी कीमत 210 रुपए से 240 रुपए पहुंच सकती है। इस बीच रिटेल इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म Bizom के आंकड़ों के मुताबिक देश में फरवरी में खाने के तेल की कीमत में तेजी आई। इनमें ब्रांडेड सनफ्लावर, वनस्पति, सरसों और मूंगफली का तेल शामिल है। यूक्रेन और रूस दुनिया में सनफ्लावर ऑयल के सबसे बड़े सप्लायर हैं। भारत में हर साल 25 से 30 लाख टन सनफ्लावर ऑयल की खपत होती है। इसका करीब 70 फीसदी यूक्रेन से आता है। 2021 में भारत के कुल खाद्य तेल आयात में यूक्रेन और रूस की हिस्सेदारी 13 फीसदी थी। भारत ने इन दो देशों से 16 लाख टन खाद्य तेल खरीदा था।

फरवरी में महंगा हुआ खाद्य तेल

फरवरी में देश में सनफ्लावर ऑयल की कीमत में पिछले महीने के मुकाबले चार फीसदी की तेजी आई जबकि सरसों के तेल की कीमत 8.7 फीसदी बढ़ी। इस दौरान सोयाबीन तेल की कीमत में 0.4 फीसदी की गिरावट आई जबकि वनस्पति तेल की कीमत 2.7 फीसदी बढ़ी। मूंगफली का तेल भी एक फीसदी बढ़ गया जबकि देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पाम ऑयल में 12.9 फीसदी गिरावट आई। फरवरी, 2020 की तुलना में पाम ऑयल की कीमत अब भी 22.9 फीसदी अधिक है।

किस देश से कौन सा तेल होता है आयात?

भारत मुख्य रूप से रूस और यूक्रेन से सनऑयल का आयात करता है। इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल का आयात किया जाता है, जबकि सोया तेल का बड़ा हिस्सा अर्जेंटीना और ब्राजील से प्राप्त होता है। वनस्पति तेल ब्रोकरेज और कंसल्टेंसी फर्म सनविन ग्रुप के मुख्य कार्यकारी संदीप बाजोरिया ने कहा कि भारत अब अर्जेंटीना से सूरजमुखी के तेल के आयात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बाजोरिया ने कहा कि, 'रूस और अर्जेंटीना से आयात के बाद भी, सनऑयल की कमी होगी। कोई भी यूक्रेन के शिपमेंट की जगह नहीं ले सकता है।'

अब भारत भरेगा दुनिया का पेट

इस साल होगा गेहूं का रिकॉर्ड निर्यात

नयी दिल्ली। एजेंसी

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण दुनियाभर में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत के पास गेहूं के बफर स्टॉक होने की खबरों से इन कीमतों पर लगाम लगी है। भारत के पास फिलहाल 12 मिलियन टन निर्यात लायक गेहूं का स्टॉक है। इस साल भारत दुनिया के उन देशों को गेहूं निर्यात करेगा, जो पहले रूस और यूक्रेन से गेहूं लेते थे। इन देशों में दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक मिस्र भी शामिल है। दुनियाभर के खाद्य वस्तुओं पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में विश्वभर में रूस-यूक्रेन युद्ध, अकाल और मांग बढ़ने के कारण भारी बढ़ोतरी हुई है। शिकागो में बेंचमार्क गेहूं के भाव ₹13.635 प्रति बुशेल के उच्चतम स्तर को पिछले महीने ही छू चुके हैं। भारत के गेहूं निर्यात करने से विश्व बाजार में गेहूं की सप्लाई बढ़ेगी। इस खबर से कीमतों में बढ़ौतरी रुकी है।

भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। ब्लूमबर्ग सर्वे के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के पास निर्यात करने लायक 12 मिलियन टन गेहूं है। अमरीकी कृषि विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 8.5 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया था। सप्लाई कम

होने और गेहूं की कीमतें बढ़ने के साथ ही बहुत से देश पहली बार भारत से गेहूं का आयात करेंगे। पिछले पांच फसली सीजन से भारत में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हो रहा है। इस कारण भारत के पास गेहूं का पर्याप्त अतिरिक्त भंडार है जिसका वह निर्यात कर सकता है। इस बार का गेहूं कटाई सीजन भी अब शुरू हो गया है। इस बार भी रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। गेहूं निर्यात को लेकर भारत की गेहूं के सबसे बड़े आयातक मिस्र के साथ बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा चीन, तुर्की, बोसनिया, सूडान, नाइजीरिया और ईरान भी गेहूं लेने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। पिछले दस महीनों में ही भारत के गेहूं निर्यात में चार गुणा बढ़ोतरी हुई है। बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत को बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के अलावा अब अफ्रीका और मिडल ईस्ट रीजन में भी निर्यात गेहूं निर्यात के मौके मिलेंगे।

भारत देगा दुनिया को राहत

एक रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर स्थित अनाज की बड़ी आयात-निर्यात फर्म एग्रीकूप इंटरनेशनल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय अयंगर का कहना है कि भारत के गेहूं निर्यात करने से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गेहूं की सप्लाई कुछ सामान्य होगी। फिलहाल सप्लाई बहुत कम है। अयंगर का कहना है कि भारत के गेहूं निर्यात करने की संभावनाओं ने ही कीमतों पर कुछ लगाम लगाई है। अगर भारत गेहूं निर्यात नहीं करता तो गेहूं की कीमतों में भारी उछाल आता। अयंगर का कहना है कि अब हालात यह है कि हर गेहूं आयातक देश भारत से गेहूं लेने पर विचार कर रहा है। अयंगर ने ये भी कहा कि भारतीय गेहूं को लेकर जितना उत्साह इस बार देखा जा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है।

कल के बाद लगातार 5 दिन तक बंद रहेंगे बैंक

नयी दिल्ली। एजेंसी

कल के बाद हम इस साल के चौथे महीने यानी अप्रैल 2022 में प्रवेश कर जाएंगे। अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। वहीं, महीने की शुरुआत बैंकों की छुट्टियों से हो रही हैं। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही लगातार 5 दिन तक अलग-अलग शहरों में बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको बैंक ब्रांच संबंधित कोई जरूरी काम है तो उसे समय रहते आज और कल में ही पूरा कर लें वरना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कब किस शहर में और क्यों बंद रहेंगे बैंक...

5 दिन बंद रहेंगे बैंक

1 अप्रैल – बैंक खातों की सालाना क्लोजिंग- लगभग सभी राज्यों में बैंक बंद।

2 अप्रैल – गुड़ी पाड़वा/उगाडी फेस्टिवल/नवरात्रि का पहला दिन/ तेलुगू नववर्ष/सजिबू नोंगमपांबा (चैरोबा)- बेलापुर, बेंगलूरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंफाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पणजी और श्रीनगर में बैंक बंद।

3 अप्रैल – रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

4 अप्रैल – सरिहुल- रांची में बैंक बंद।

5 अप्रैल – बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन- हैदराबाद में बैंक बंद।

अप्रैल में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक अप्रैल में बैंक कुल 15 दिन बंद रहेंगे। इनमें साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं।

भेल को इराक से कंप्रेसर आपूर्ति का ठेका मिला

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को इराक से कंप्रेसर आपूर्ति का ठेका मिला है। इराक के तेल मंत्रालय के अधीन आने वाली राष्ट्रीय तेल रिफाइनरी कंपनी 'नदर्न रिफायनरीज कंपनी (एनआरसी)' ने यह ऑर्डर बैजी रिफाइनरी के लिए दिया है। भेल ने एक बयान में कहा कि इराक से कंप्रेसर आपूर्ति का बड़ा ऑर्डर मिलने के साथ कंपनी को अंतरराष्ट्रीय कारोबार में एक और उपलब्धि हासिल हुई है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर चालित कंप्रेसर की डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण एवं आपूर्ति करना शामिल है। इससे पहले 2000 में इराक को भेल ने ही कंप्रेसर की आपूर्ति की थी, नया कंप्रेसर उसी का स्थान लेगा। पुराना कंप्रेसर इराक में युद्ध के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेल अब तक फ्रांस, बांग्लादेश, इराक, ईरान, ओमान और बेलारूस को कंप्रेसर की आपूर्ति कर चुकी है। बयान में बताया गया कि कंपनी की 88 देशों में मौजूदगी है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।